



न्यूज़ ब्रीफ

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को नवाचारपूर्ण एचआर प्रथाओं के लिए सम्मान



नई दिल्ली। बेंगलुरु में आयोजित 25वें एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस अवार्ड्स 2026 में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को दो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। कंपनी को नेतृत्व विकास, संगठनात्मक क्षमता, कार्यस्थल संस्कृति, कर्मचारी अनुभव और प्रतिभा विकास की पहलों के लिए 'टॉप ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिसेज' सम्मान दिया गया। वहीं, कंपनी के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी ज्वा नाम किम को मानव संसाधन बदलाव और कर्मचारी-केंद्रित कारोबारी विकास में नेतृत्व के लिए 'मोस्ट इम्पैक्टफुल एचआर लीडर अवार्ड' से नवाजा गया। किम ने सम्मान को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के सभी कर्मचारियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी की मानव संसाधन पहल कारोबारी बदलाव से जुड़ी हैं और भविष्य के लिए नेतृत्व, क्षमताओं व कार्यसंस्कृति को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। कंपनी को 2024 और 2025 में लगातार 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' प्रमाणन भी मिला है।

अमेरिकी फेड ने फिर बढ़ाई ब्याज दरें, महंगा होगा कर्ज; महंगाई से जंग लंबी



नई दिल्ली। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। देश में लगातार बनी हुई ऊँची महंगाई दर को नियंत्रित करने के मकसद से लिए गए इस फैसले के बाद अब अमेरिकी ब्याज दरें 3.75 से 4 फीसदी के दायरे में आ गई हैं। फेड ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में कर्ज और महंगा हो सकता है, क्योंकि महंगाई से लड़ाई उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी खिंच सकती है। केविन वार्श के फेड चेयरमैन बनने के बाद यह पहली बढ़ोतरी है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से कम ब्याज दरों के पक्षधर रहे हैं, महंगाई के दबाव में फेड को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है। फेड के नए अनुमान बताते हैं कि ब्याज दरों में यह वृद्धि यहीं नहीं थमेगी; 18 में से 16 अधिकारियों का मानना है कि साल के अंत तक दरें कम से कम 0.25 फीसदी और बढ़ सकती हैं, जिससे वे 4 से 4.25 फीसदी के दायरे में पहुंच जाएंगी। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि महंगाई को 2 फीसदी के लक्ष्य तक लाने में 2029 तक का समय लग सकता है, जो पहले 2028 तक का अनुमान था। 2026 में इसके 3.7 फीसदी रहने की आशा का है। ट्रंप के आयात शुल्क, पश्चिम एशिया में तनाव के कारण महंगा हुआ तेल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश को महंगाई के प्रमुख कारक बताया जा रहा है।

टोयोटा की चार लोकप्रिय कारों के फेसलिफट माडल जल्द होंगे पेश



नई दिल्ली। भारतीय बाजार में टोयोटा कंपनी जल्द ही अपनी चार लोकप्रिय कारों के फेसलिफट माडल पेश करने की तैयारी में है। इन में ग्लैंजा, इनोवा हाइक्रास, टाइनजर और अर्बन क्रूजर हाइराइडर शामिल हैं, जो अपने ग्राहकों को बेहतर डिजाइन, उन्नत फीचर्स और कुछ मामलों में नए इंजन विकल्प भी प्रदान करेंगी। मारुति सुजुकी बलेनो के अपडेट के बाद, टोयोटा ग्लैंजा का फेसलिफट माडल अक्टूबर 2026 में लान्च होने की उम्मीद है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, बदले हुए बॉर, नए अलाय व्हील और लाइटिंग में छोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। फीचर्स के मामले में, इसमें लेवल 2 एडीएएस, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, 9-इंच टचस्क्रीन और 6 एयरबैग जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इसका इंजन मौजूदा 4-सिलेंडर यूनिट की जगह एक नए 1.2-लीटर, 3-सिलेंडरU Z12E पेट्रोल इंजन में बदल सकता है, जिसे मेनुअल और एएमटी गियरबाक्स के साथ पेश किया जाएगा।

नईदुनिया

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली
घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। कीमत में उछाल आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 270 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 290 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया। वहीं चांदी के भाव में लगातार चौथे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये चमकौली धातु भी शुरुआती कारोबार के दौरान स्तर पर ही कारोबार कर रही है।
कीमत में हुए इस बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,53,450 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,53,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना

1,40,660 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,40,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकौली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।
दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,53,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,810 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,53,450 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,40,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत

1,40,710 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,53,450 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,40,660 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,53,450 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,40,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,40,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।
जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,53,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,40,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,500

रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,40,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,53,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,40,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोना मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,53,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोना 1,40,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला एनएसई का आईपीओ, ग्रे मार्केट के निगेटिव रिस्पान्स के कारण बोली लगाने से डर रहे निवेशक

नई दिल्ली
निवेशकों के लंबे इंतजार के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 21 सितंबर तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 22 सितंबर को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 23 सितंबर को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 24 सितंबर को बीएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। लान्चिंग के बाद दोपहर 12 बजे तक ये आईपीओ सिर्फ 22 प्रतिशत ही सब्सक्राइब हो सका था।

माना जा रहा है कि ग्रे मार्केट से मिले निगेटिव रिस्पान्स की वजह से निवेशक काफी सतर्क हो कर इस आईपीओ के लिए बोली लगा रहे हैं। ग्रे मार्केट में एनएसई के शेयर की मांग लगातार कमजोर होती गई है। पांच सितंबर को ग्रे मार्केट में इस शेयर के लिए 310 रुपये यानी 17.37 प्रतिशत प्रीमियम मिल रहा था, लेकिन उसके बाद से इस शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार गिरता चला गया। लान्चिंग के दिन दोपहर 12 बजे ग्रे मार्केट में ये शेयर सिर्फ 137 रुपये यानी 7.68 प्रतिशत प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। ग्रे मार्केट प्रीमियम में आई गिरावट की वजह से निवेशक अब इस आईपीओ में बोली लगाने से हिचक रहे हैं।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 1,700 रुपये से लेकर 1,785 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइड 8 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम एक लाट यानी 8 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,280 रुपये का निवेश करना होगा।

इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 9,920 रुपये के निवेश से अधिकतम 14 लाट में 112 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत एक रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 12,64,36,650 शेयर आफर फार सेल विंडो के जरिये बेजे जा रहे हैं।

इस आईपीओ में बवालफाइंड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 35 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि



एमयूजीएफ इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर बनाया गया है।

एनएसई की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबो के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद लगातार मजबूत बनी रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 8,305.74 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 12,187.69 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ थोड़ा कम होकर 10,302.06 करोड़ रुपये हो गया। मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 की बात करें तो पहली तिमाही के अंत यानी 30 जून 2026 तक एनएसई को 3,120.08 रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका था।

इस दौरान एनएसई की राजस्व प्रॉसि में भी मामूली उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 16,352.06 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 19,176.83 करोड़ रुपये और 2025-26 में थोड़ा फिसल कर 18,713.37 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 की बात करें तो पहली तिमाही के अंत यानी 30 जून 2026 तक एनएसई को 5,252.17 करोड़ रुपये का राजस्व मिल चुका था।

एनएसई के रिजर्व और सरप्लस में इस अवधि को दौरान लगातार बढ़ोतरी होती रही। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 23,924.91 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 30,105.83 करोड़ रुपये के स्तर पर और 2025-26 में बढ़ कर 31,866.04 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 की बात करें तो पहली तिमाही के अंत यानी 30 जून 2026 तक एनएसई का रिजर्व और सरप्लस 34,996.73 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा हुआ था।

इस अवधि में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्थ में भी लगातार बढ़ोतरी होती रही। वित्त वर्ष 2023-24 में एनएसई का नेटवर्थ 23,833.10 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 30,165.05 करोड़ रुपये के स्तर पर और पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में उछल कर 31,869.72 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के अंत यानी 30 जून 2026 तक एनएसई का नेटवर्थ 94,983.74 करोड़ रुपये हो गया था।

इसी तरह एनएसई का ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंस्ट्रेट, टैक्सज, डिप्रेशिएशंस एंड एमप्टाईजेशन) 2023-24 में 11,623.83 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 16,021.36 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

केंद्र ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विडफाल टैक्स घटाया, नई दरें लागू



नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विडफाल) टैक्स में कटौती की है। नई दरें लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि 16 सितंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विडफाल) टैक्स में कटौती की गई है। शुल्क की नई दरें प्रभावी हों गई हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक डीजल के निर्यात पर सड़क पुनर्निर्माण ढांचा उपकरण समेत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएसईडी) की दर अब 25 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएसईडी 19 रुपये से घटाकर 15 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पिछले पखवाड़े में 1.5 रुपये प्रति लीटर था।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली
ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जॉन्स स्पूचर्स मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। वहीं एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा पिछले तीन साल से अधिक समय में पहली बार ब्याज दर बढ़ाने और आगे भी सख्ती करने का संकेत देने के कारण बाल स्ट्रीट में पिछले सत्र के दौरान निवेशक सतर्क होकर कारोबार करते हुए नजर आए। महंगाई बढ़ने की आशंका के कारण अमेरिकी बाजार के सूचकांक गिरावट का शिकार हो गए। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 631.33 अंक यानी 1.21 प्रतिशत फिसल कर 51,461.78 अंक के स्तर पर आ गया।
इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.45



प्रतिशत टूट कर 7,551.81 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डैक 0.01 प्रतिशत की संकेतिक कमजोरी के

के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान तेजी का रुख बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.28 प्रतिशत उछल कर 10,688.47 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसई इंडेक्स ने 0.62 प्रतिशत की छलांग लगा कर 8,140.59 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डीएएस इंडेक्स 135.47 अंक यानी 0.53 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,537.75 अंक के स्तर पर बंद हुआ। झ
एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से छह के सूचकांक मजबूती के साथ रहे निरान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि तीन सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। हंग सेंग इंडेक्स 206.78 अंक यानी 0.84 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,507 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कर्सी तरह शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.36 प्रतिशत फिसल कर 3,877.46 अंक के स्तर पर

आ गया है। इसके अलावा जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.12 प्रतिशत लुढ़क कर 6,429.17 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। दूसरी ओर, गिफ्ट निफटी 0.11 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,292.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स 369 अंक यानी 0.57 प्रतिशत उछल कर 64,292 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। ताइवान वेटेड इंडेक्स में जोरदार तेजी नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 605.33 अंक यानी 1.30 प्रतिशत की छलांग लगा कर 46,454.23 अंक के स्तर पर आ गया है। सेट कंपोजिट इंडेक्स ने भी शानदार तेजी दिखाई है। फिलहाल यह सूचकांक 0.88 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,576.67 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा कोस्पी इंडेक्स 0.40 प्रतिशत की मजबूती के साथ 6,745.11 अंक के स्तर पर और स्टूट्स टाइम्स इंडेक्स 0.03 प्रतिशत की मामूली उछाल के साथ 5,651.70 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

लोन जमा नहीं होने पर बैंक या एनबीएफसी गाड़ी को जबरदस्ती नहीं उठा सकते



नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक या एनबीएफसी को गाड़ी वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन वे इसके लिए मनमाना या जबरदस्ती का तरीका नहीं अपना सकते। गाड़ी जब्त करने से पहले तय प्रक्रिया और उचित नोटिस का पालन करना होगा यानी सिर्फ ईएमआर नहीं भरने का मतलब यह नहीं है कि फाइनेंस कंपनी रात में गाड़ी उठाकर ले जाए।

बता दें यह मामला यूपी के एक ट्रक मालिक से जुड़ा है। उसने कर्मशियल ट्रक खरीदने के लिए चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। कुछ समय बाद वह किस्तें नहीं चुका पाया। कंपनी ने नोटिस दिया और ट्रक अपने कब्जे में ले लिया। बाद में ग्राहक ने एकमुश्त रकम जमा की तो उसे ट्रक वापस मिल गया। इसके बाद फिर लोन की किस्तें नहीं चुकाई गईं। ग्राहक के मुताबिक 9 अप्रैल 2023 की रात करीब एक बजे अयोध्या में सामान पहुंचाने के बाद खड़े ट्रक में, स्ट्रीयरिंग लाक चार अज्ञात लोगों ने तोड़ा और ट्रक लेकर चले गए। उसका कहना था कि उसे इस कार्रवाई से पहले नोटिस नहीं दिया गया था। बाद में ट्रक बेच दिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गाड़ी जब्त करने से पहले तय प्रक्रिया का पालन करना होगा

पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि फाइनेंसर के पास लोन की शर्तों के तहत गाड़ी वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस अधिकार का मतलब यह नहीं है कि बैंक या फाइनेंस कंपनी बल प्रयोग करके या चोरी-छिपे वाहन कब्जे में ले सकती है।

कोर्ट ने साफ किया कि वसूली के लिए कानूनी रास्ता अपनाना होगा। रात में ताला तोड़ना, जबरदस्ती गाड़ी ले जाना या लोगों के जरिए दबाव बनाना सही तरीका नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में कंपनी को ग्राहक के अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। आरबीआई के साथ 9 अप्रैल 2023 में भी लोन वसूली के दौरान ग्राहक को अनावश्यक रूप से परेशान करने, गलत समय पर संपर्क करने और बल प्रयोग करने से बचने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को इन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है।

एमडीआर लागू होने से डिजिटल भुगतान और बैंकिंग उद्योग की आय में होगी बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2027-28 में करीब 180 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान

नई दिल्ली
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर छह साल बाद एक बार फिर मचेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने से डिजिटल भुगतान और बैंकिंग उद्योग की आय में 15,000 से 20,600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। यह अनुमान ब्रोकरेज कंपनियों ने लगाया है। एमडीआर वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए दुकानदारों से लिया जाता है। एमडीआर 2,000 रुपए से ज्यादा के पीयर-टू-मचेंट (पी2एम) यानी ग्राहक से कारोबारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लागू होगा। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 26 अगस्त के लेनदेन स्तर को आधार मानें तो कुल यूपीआई पी2एम लेनदेन मूल्य का करीब 48 फीसदी हिस्सा एमडीआर के दायरे में आता है। इससे उद्योग के लिए करीब 20,600 करोड़ रुपए की आय का मोका है।

सिटी ने सालाना 16 से 17 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया है। वहीं, जेफरीज ने उद्योग के लिए 15 से 18 हजार करोड़



रुपए की आय का होने की संभावना बताई है।
मोडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमडीआर से होने वाली आय यूपीआई व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग पक्षों के बीच बांटी जाएगी। इनमें पीएसपी बैंक, यूपीआई ऐप प्रदाता के साथ वे दोनों बैंक शामिल हैं जिनसे रकम निकलेगी और जिनमें रकम पहुंचेगी। गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक कुल आय में से 50 फीसदी हिस्सा भुगतान जारी करने वाले बैंकों और पीएसपी को, 20 फीसदी थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता को और 30 फीसदी भुगतान लेने वाले बैंकों को मिलेगा।

सिटी के अनुमान के मुताबिक अतिरिक्त आय का करीब 60 फीसदी हिस्सा जारी करने वाले और लेने वाले बैंकों या यूपीआई हैंडल के जरिये बैंकिंग क्षेत्र को मिलेगा। करीब 25 फीसदी आय यूपीआई ऐप प्रदाताओं और बाकी 15 फीसदी गैर-बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को मिलने की संभावना है। निजी क्षेत्र के एक बैंक के वरिष्ठ बैंकर ने कहा

कि जिन बैंकों के साथ अपेक्षाकृत अधिक राशि के लेनदेन करने वाले कारोबारी जुड़े हैं, उन्हें फायदा हो सकता है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कारोबारी को लेनदेन की कुल रकम का अधिकतम 0.40 फीसदी एमडीआर के रूप में देना होगा। इस शुल्क को यूपीआई से जुड़े अलग-अलग पक्षों के बीच बांटा जाएगा। मसलन अगर यूपीआई से 10,000 रुपए का लेनदेन होता है तो कारोबारी को 40 रुपए एमडीआर देना होगा। इसमें से भुगतान स्वीकार करने वाले बैंक को 40 रुपए मिलेंगे। वह इसमें से 28 रुपए भुगतान जारी करने वाले बैंक को देगा और उसके पास 12 रुपए बचेंगे। भुगतान देना करने वाले बैंक को मिले 28 रुपए में से वह 12 रुपये भुगतानकर्ता के पीएसपी को देगा। इस तरह उसके पास 16 रुपए बचेंगे। पीएसपी को मिले 12 रुपए में से वह 8 रुपए यूपीआई ऐप प्रदाता को देगा और उसके पास 4 रुपए बचेंगे। इस तरह 40 रुपए के कुल एमडीआर में से भुगतान लेने वाले बैंक को 12 रुपए, देने वाले बैंक को 16 रुपए, भुगतानकर्ता के पीएसपी को 4 रुपए और ऐप प्रदाता को 8 रुपए मिलेंगे। यूपीआई व्यवस्था में एसबीआई सबसे बड़ा भुगतान जारी करने वाला बैंक है। इसके बाद बैंक आफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, फिनियन बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक और अन्य बैंक हैं।